नगर निगम शिमला

संजय चौहान

महापौर

का

वर्ष 2014-2015 की बजट बैठक पर

भाषण

22 फरवरी, 2014

अनुक्रमणिका

क्र0स0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	बजट अभिभाषण	1
2.	वित्तीय स्थिति	2
3.	कर्मचारी हितो के कार्य	5
4.	मार्ग एवं भवन	6
5.	सोलर सिटी	12
6.	शहरी गरीब के लिए परियोजना	13
7.	अन्य परियोजनाएं	14
8.	जल विभाग	17
9.	स्वास्थ्य विभाग	19
10.	सम्पदा विभाग	20
11.	वास्तुक विभाग	22
12.	स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना	22
13.	सूचना प्रोद्यौगिक व ई0 गवर्नेस	23
14.	प्राप्त सहायता अनुदान	24
15.	विकासात्मक गतिविधियों के लिए बजट	25
16.	नगर निगम शिमला के वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान	26

बजट अभिभाषण 2014-15

सम्माननीय्

मैं आप सभी का वर्ष 2014-2015 के बजट बारे हो रही इस ' विशेष बैठक ' में स्वागत करता हूँ।

नगर निगम शिमला का यह वार्षिक बजट ऐसे दौर में पेश किया जा रहा है जब पूरी दुनियाँ खासतौर पर विकसित पूंजीवादी देश गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रह है। हमारा देश भारत भी कमोवेश ऐसे ही संकट का सामना कर रहा है। इसका असर सबसे अधिक आम जनमानस पर ही पड़ता है और पड़ रहा है । विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों से जाहिर हो गया है कि अमीर और गरीब की खाई गहराती ही जा रही है।

प्रदेश में भी विकास की आर्थिक दर में गिरावट आई है। हमारी आर्थिकी के असर से आम जनमानस की हालत में बढ़ौतरी के बजाए संकुचन हुआ है, जिससे जनता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

शिमला में रहने वाली जनता भी इस प्रक्रिया से अछूती नहीं है। अतः इस परिपेक्ष में हम मौजूदा बजट से कोई अन्य बोझ आम जनमानस पर नहीं डालना चाहते और अपने दायरे में आने वाली जिम्मेवारी से कुछ राहत और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहते है।

इस चालू वर्ष में अभी तक 10 साधारण बैठकें, 9 साधारण कृत्यकारक समिति की बैठके , 12 वित्त, संविदा और योजना समिति की बैठकें, 7 सामाजिक एवं न्याय समिति की बैठकें तथा 3 विशेष बैठकें हो चुकी है। इन बैठकों में माननीय पार्षदगणों ने शिमला शहर के विकास, जनता को आवश्यक मूलभूत सेवाओं की बेहतरी व जनहित में अनेक मुद्दो पर चर्चा की गई तथा अपने-अपने प्रस्ताव व सुझाव रखे। जिसके आधार पर शहर के विकास के लिए निर्णय लिए गए।

वित्तीय स्थिति :

जैसा कि विदित है कि यह हमारी छठवीं निर्वाचित नगर निगम का द्वितीय बजट प्रस्तुतीकरण है । मान्य सदन के समस्त सदस्यगण नगर निगम की वित्तीय स्थिति से भली-भान्ति परिचित है । नगर निगम की आय के स्त्रोत सीमित होने के कारण शहर में विकास जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप करने में कठिनाई आ रही है । चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2013 तक निगम के अपने स्त्रोतों से 3380.02 लाख रूपये की आय और अनुदान से राशि 2817.01 लाख रूपये अर्थात कुल राशि 6197.03 लाख रूपये की प्राप्ति हुई है । जबकि चालू वित्त वर्ष में निगम को कुल व्यय राशि 5991.16 लाख रूपये हुआ है। निगम की आय व व्यय में बढ़ते अन्तर से विकास को सही दिशा देने में कठिनाई आ रही है ।

नगर निगम की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु गत वित्त वर्ष में जो कदम उठाये उसमें सरकार से अतिरिक्त अनुदान सहायता का अनुरोध किया गया था। जिसमें मुख्यतः 100 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष राजधानी विकास अनुदान (Capital Development Grant), चुंगी समाप्ति के बदले प्रतिभूति /डवैल्पमेण्ट ग्रॉट को नगर निगम के कुल व्यय का 50 प्रतिशत करना,निगम सीमा में मिलाए गए नए क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान राशि 600.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष, पानी की बल्क खरीद के बिलों की बकाया देय राशि के भुगतान हेतु विशेष अनुदान राशि, शहरी वनों तथा शहर के विभिन्न मार्गो के रख-रखाव, राज्य विद्युत बोर्ड को देय बकाया व वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निगम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हेतु विशेष अनुदान राशि प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया था। परन्तु इस बारे सरकार द्वारा आशातीत कदम नहीं उठाए गए है। शिमला शहर का ऐतिहासिक व सामरिक गौरव को बनाए रखने के लिए सरकार नगर निगम के इस अनुरोध पर गहनता से विचार करेगी तथा इन अनुदानों को उपलब्ध करवायेगी।

नगर निगम शिमला के द्वारा आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए प्रदेश के बाहर रजिस्ट्रड़ वाहनों के प्रवेश पर ग्रीन फीस लगाकर प्रतिवर्ष 600.00 लाख रूपये की आय का प्रावधान था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसके एकत्रित करने हेतु किए गए प्रबन्धों में सुधार करने के आदेश के कारण इसे बन्द करना पड़ा। नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को पालन करते हुए इसे पुनः आरम्भ किया जाएगा।

नगर निगम की मुख्य आय का स्त्रोत सम्पति कर है । परन्तु जे.एन.एन.यू. आर.एम. के अर्न्तगत वांछित सुधारो के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधित करके निगम सीमा में युनिट एरिया मैथड़ पर सम्पति कर लगाने हेतु दिनांक 20 फरवरी, 2012 को अधिसूचना जारी की गई है। परन्तु माननीय सदन ने सर्व-सम्मति से युनिट एरिया मैथड़ की कर प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव पारित कर पुनः सरकार से अनुरोध किया है कि हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन करके सम्पति कर लगाने का युक्तिकरण किया जाए जिससे न तो भवन स्वामियों को सम्पति कर का अतिरिक्त बोझ पड़े और निगम की करों से आय भी बढ़ाई जा सके तथा पुनः आग्रह किया जाता है कि जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता तब तक नगर निगम शिमला द्वारा पुरानी पद्धति पर सम्पति कर लगाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

74वें सवैधानिक संशोधन के 12वें शैडयूल के अर्न्तगत शहरी निकाय को दिए गए उत्तरदायित्वों में शहरी वानिकी का प्रबन्धन भी सम्मिलित है । इसके अनुसार शिमला शहर व इसके साथ लगते वनों के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व शिमला नगर निगम का बनता है। परन्तु सरकार ने वर्तमान मे शहरी वन का क्षेत्राधिकार नगर निगम से अपने अधीन हस्तांतरित कर दिया है। अतः सरकार से अनुरोध है कि पूर्व मे अधिकृत शहरी वन क्षेत्र को नगर निगम शिमला को पुनः लौटाया जाए तथा इससे होने वाली आय को भी

नगर निगम शिमला को उपलब्ध करवाया जाए ताकि इन वनों का उचित व विज्ञानिक प्रबन्धक किया जा सके।

नगर निगम की कार्य प्रणाली मे जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 74वें सवैधानिक संशोधन को ध्यान मे रखते हुए हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1994 मे वार्ड सभाओं मे वार्ड कमेटियों के गठन पर बल दिया गया है। परन्तु अभी केवल 5 वार्डो मे ही वार्ड कमेटियों का गठन किया गया है। शेष बचे वार्डो में इनका शीघ्र गठन किया जाएगा ताकि शहर के विकास की योजना में जनता का सहयोग सुनिश्चित हो पाए। इन वार्ड सभाओं के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजना बनाई जाएगी तथा इसके लिए प्रति वार्ड 25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक निर्वाचित तथा नामांकित पार्षद की अनुशंसा पर रू. 5 लाख की धनराशि वार्डो में विकास कार्यो के लिए प्रदान की गई है, जिसे आगामी वर्ष में रू. 10 लाख कर दिया जाएगा। धन की उपलब्धता पर उपरोक्त राशि के अतिरिक्त रू. 25 लाख प्रति वार्ड की राशि सम्बन्धित पार्षद की अनुशंसा पर खर्च करने की प्रस्तावना है।

जवाहर लाल नहेरू शहरी नवीकरण मिशन के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा पेयजल योजना के कायाकल्प तथा मल निकास प्रणाली के नवीकरण एवं जिन क्षेत्रों में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, वहॉ पर सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु परियोजना जिसका निर्माण पी.पी.पी. के आधार पर करवाना तय किया गया था, का मामला प्रदेश सरकार से उठाया गया था। इस परियोजना को नगर निगम द्वारा स्वयं कार्यान्वित करने की मांग उठाई गई थी । इस मांग को प्रदेश सरकार ने मान लिया है तथा अब इस परियोजना का निर्माण नगर निगम शिमला व सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से EPC Mode से किया जाएगा । इसकी संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) 127 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 307.28 करोड़ रूपये नगर निगम शिमला ने पारित करके

केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। स्वीकृति प्रदान होते ही इस परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।

नगर निगम शिमला द्वारा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को देय बकाया को पूर्ण भुगतान कर दिया है । इसके लिए 4.33 करोड़ रू. का भुगतान वर्ष 2013-14 में किया गया है ।

कर्मचारी हितों के कार्य :

- कर्मचारी नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है। वर्तमान में नगर निगम द्वारा 1189 स्थायी/अनुबन्धित/दैनिक वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारियों को वेतन-भत्ते/मानदेय/ दिहाड़ी तथा 435 पैन्शनधारकों को पैन्शन की अदायगी की जा रही है। वित्त वर्ष 2013-14 में लगभग रू. 41 करोड़ के व्यय की अपेक्षा 2014-15 में लगभग रू. 46 करोड़ के व्यय का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष में निगम के सेवानिवृत/मृतक कर्मचारियों के संदर्भ में लम्बित सभी वित्तीय लाभ जारी करने का लक्ष्य है। अप्रैल, 2014-15 से सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को चिक्तिसा प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए वार्षिक लगभग रू. 30 लाख का व्यय होगा। बालूगंज-पड़ाव तथा कोटहिल में कर्मचारियों के आवासीय परिसरों का निर्माण प्रस्तावित है।

- वर्तमान में नगर निगम कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है और इस समय निगम में अधीक्षक ग्रेड -I के 3 पद, अधीक्षक ग्रेड -II के 6 पद , वरिष्ठ सहायक के 5 पद, लिपिकों के 30 पद तथा सफाई स्टाफ के 100 पद रिक्त पड़े है। स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी निगम प्रशासन का यथासम्भव प्रयास रहता है कि लोगों की आकांक्षा के अनुरूप मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाये।रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार से मिलकर आग्रह किया गया था कि इन्हें भरने के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे। सरकार से स्वीकृति मिलते ही रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरा जाएगा।

माननीय सदस्यगण इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यो एवं लक्ष्यों का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है :-

1. मार्ग एवं भवन :

- नगर निगम द्वारा ऑकलैण्ड शॉपिग कम्पलैक्स में 20 दुकानों का निर्माण किया गया जिसकी लागत 34,53,944/- रू. आई है । इन दुकानों को वार्षिक किराये पर दिया गया है । जिससे नगर निगम को इस वित्त वर्ष में 18 लाख 54 हजार 750 रूपये की आय हुई है तथा हर तीसरे वर्ष इन दुकानों के किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी। इसके अतिरिक्त इन दुकानों से लीज के रूप में एक मुश्त रू. 1 करोड़ 47 लाख की आय हुई है।

- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली के समीप 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र पर रू. 24 करोड़ 70 लाख की अनुमानित लागत से 400 वाहनों के लिए पी.पी.पी. आधार पार्किंग का निर्माण प्रगति पर है। इसमें लगभग 40 हजार वर्ग फुट व्यवसायिक क्षेत्र प्रस्तावित है। 30 वर्षो की कन्सैशन (Concesseion) अवधि में नगर निगम को प्रति वर्ष रू. 96 लाख की आमदनी होगी, जो प्रति 2 वर्षो में 10 प्रतिशत बढ़ेगी। प्रस्तावित नौ मंजिला परिसर वाले भवन में से लगभग 150 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाली तीन मंजिलों को शीघ्र ही जनसाधारण के लिए खोल दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2014-15 में सम्पूर्ण रूप से कार्य कर लिया जाएगा।

- लिफ्ट के समीप 6471.24 वर्गमीटर क्षेत्र रू. 46 करोड़ 11 लाख की अनुमानित लागत से 700 वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 30 वर्षो की कन्सैशन (Concession) अवधि में नगर निगम को प्रतिवर्ष रू. 1 करोड़ की आय होगी जोकि प्रति 2 वर्षो में 10 प्रतिशत बढ़ेगी,परिसर में 40 हजार वर्गफुट व्यवसायिक क्षेत्र बनाया जाएगा। छः मंजिला निर्माणाधीन परिसर की चार मंजिलें वित्त वर्ष 2014-15 के अन्त तक पूर्ण हो जाएगी।

- छोटा शिमला में 1832 वर्ग मीटर क्षेत्र में रू. 11 करोड़ 68 लाख की अनुमानित लागत से 250 वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण पी.पी.पी. आधार पर प्रगति पर

है। 30 वर्षो की कन्सैशन (Concession) अवधि में नगर निगम को रू. 36 लाख प्रतिवर्ष की आय होगी, जोकि प्रति दो वर्षो में 10 प्रतिशत बढ़ेगी। परिसर में 30 हजार वर्गफुट व्यवसायिक क्षेत्र प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 के अन्त तक आठ मंजिला परिसर पूर्ण किया जाएगा।

- विकासनगर में 1062 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 174 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले परिसर का निर्माण कार्य मार्च, 2014 मे प्रारम्भ किया जा रहा है। 40 वर्षो के कन्सैशन(Concession) अवधि में नगर निगम शिमला को प्रतिवर्ष रू. 16 लाख आमदनी होगी, जो प्रति 3 वर्षो में 10 प्रतिशत बढ़ेगी।

- सौंदर्यकरण के दृष्टिगत रिज पर स्थित दौलत सिंह पार्क में नगर निगम द्वारा कोबल फलौरिंग करवाई गई है, जिस पर लगाभग रू. 5 लाख 53 हजार 710 व्यय होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त पार्क के सौन्दर्यकरण की दृष्टि से गेट का निर्माण और ले0 जनरल दौलत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य आर्मी द्वारा करवाया गया है।

- शहर में विभिन्न स्थानों पर 210 नई स्ट्रीट लाईट प्वाईटस लगाये जा चुके है जिस पर राशि रू. 47 लाख 44 हजार 985 व्यय किए जा चुके है तथा खराब पड़ी स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव पर राशि रू. 6 लाख 26 हजार 398 व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त 10 हाई मास्क लाईट तथा 2 लेजर लाईट लगाई जाएंगी तथा क्षेत्र विशेष में एक ही जैसी स्ट्रीट लाईटें लगाई जानी प्रस्तावित है।

- इस वित वर्ष में स्ट्रीट लाईटों के लम्बित बिलों की बकाया राशि का भुगतान हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को रू. 31.09 लाख का कर दिया गया है तथा वर्तमान में बिलो की अदायगी देय तिथि अनुसार की जा रही है।

- शहर के विभिन्न वार्डो में तारकोल का कार्य प्रगति पर है और कुछ वार्डो में कार्य पूर्ण हो चुका है । जिस पर अभी तक राशि 63 लाख 68 हजार 526 रू. व्यय किए जा चुके है ।

- सब्जी मण्डी मैदान में लगभग रू. 100 करोड़ की लागत से डी.बी.ओ.टी आधार पर HPIDB के माध्यम से प्रस्तावित बहु उद्देशीय परिसर की औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं ताकि सितम्बर, 2014 तक कार्य आरम्भ करने का लक्ष्य है। कार्य पूर्ण होने पर नगर निगम को न्यूनतम रू. 2 करोड़ प्रतिवर्ष आय का अनुमान है।
- नगर निगम के भराड़ी स्थित विश्राम गृह को पूर्ण करने के लिए, बाउण्डरी वाल, बिजली की फिटिंग, फर्नीचर की खरीद इत्यादि पर लगभग 50 लाख की लागत से कार्य किया जा रहा है। अप्रैल, 2014 से विश्राम गृह को चालू कर दिया जाएगा। विश्राम गृह का व्यवसायिक प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाएगा तथा इससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी।

- ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रमुख रूप से भूस्खलन रोकने के आश्य से एवं आय सृजन के उद्देश्य से लगभग रू. 20 करोड़ की अनुमानित लागत से पार्क, दुकानों, मल्टीपलैक्स, स्काईवाक, लिफ्ट, फूड कोर्ट इत्यादि की सुविधा से सुसज्जित बहुउद्देशीय परिसर की परिकल्पना अन्तिम चरण में है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का डिजाईन व मॉडल विकसित किया जा रहा है ताकि रिज मैदान का संरक्षण हो सके तथा जनाकर्षण का केन्द्र बिन्दु प्रस्तुत किया जा सके।

- दाड़नी का बगीचा (कनलोग) में श्मशानघाट के समीप जनसाधारण की सुविधा के लिए 50 वाहनों की पार्किंग की निशुल्क व्यवस्था जनू, 2014 तक की जाएगी। इसके अतिरिक्त लगभग रू. 2 करोड़ की लागत से आकर्षक पार्क का निर्माण आरम्भ किया जाएगा। जिसका डिजाईन तैयार किया जा रहा है।

- सतलुज जल विद्युत निगम के सौजन्य से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्क विकसित करने तथा लेण्डस्केपिंग के लिए लगभग रू. 3 करोड़ 35 लाख की धनराशि प्रदान करने की सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता है। इसके अतिरिक्त सतलुज जल विद्युत निगम लि0 द्वारा हाई मास्क लाईट, बैंच, लेजर लाईट इत्यादि भी नगर निगम को दिए गए हैं। शेष धनराशि से विकासात्मक एवं सौन्दर्यकरण के कार्यों को योजनाबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा।

- वित्त वर्ष 2014-15 में ढली में डी.बी.ओ.टी आधार पर पार्किंग सुविधा सहित बहुउद्देशीय परिसर का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। सामुदायिक भवन न्यू शिमला का विस्तारीकरण, भराड़ी में सामुदायिक भवन का निर्माण पूर्ण करना, खलीनी, चक्कर, ढली टनल के समीप तथा कैथू में बहुउद्देशीय परिसरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
- पॉंजड़ी (टूटीकण्डी) में लगभग रू. 40 लाख की लागत से पशु चिकित्सालय का कार्य वित्त वर्ष में पूर्ण कर दिया गया हैं दिनांक 3.6.2013 से 31.1.2014 तक 718 आवारा कुत्तों की नसबन्दी की गई हैं । इस संदर्भ में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया ताकि वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। वर्ष 2014-15 में लगभग 1000 आवारा कुत्तों की नसबन्दी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- नगर निगम शिमला द्वारा सब्जी मण्डी में स्थित मीट मार्किट के पुनर्निमाण हेतु डिजाईन तथा लगभग रू. 1 करोड़ 80 लाख का प्राकलन तैयार किया गया है। वर्तमान दुकानों/स्टालों की वैकल्पिक व्यवस्था एवं धन का प्रावधान करके निर्माण कार्य सितम्बर, 2014 तक आरम्भ कर दिया जाएगा।

- नगर निगम शिमला की Embassy of France के शिष्टमण्डल से हुई सकारात्मक वार्ता में ट्रामवेज, केबल कार, रोपवे, स्ट्रीट लाईट, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करने तथा समुचित वित्त पोषण पर सैद्धान्तिक सहमति हुई है। शिष्टमण्डल द्वारा निशुल्क techno-economic studies के पश्चात् औपचारिकताएं पूर्ण करके चिन्हित क्षेत्रों में उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन् दिया है, जिसे आगामी वित्त वर्ष में लक्षित गति दी जाएगी।

- नगर निगम शिमला के अर्न्तगत छः एसकेलेटरज :- (i) लिफ्ट से माल रोड़ वाया सब्जी मण्डी मैदान, (ii) लक्कड़ बाजार बस अड्डा से रिज मैदान/माल रोड़ (iii) लोअर बाजार से माल रोड़ (इन्दिरा चौक) (iv) लोअर बाजार से माल रोड़ (जैन मन्दिर के समीप) ,(v) रेलवे स्टेशन से माल रोड़ (vi) ऑकलैण्ड टनल से लक्कड़ बाजार स्थापित करने की योजना HPIDB को माननीय सदन के अनुमोदन के उपरान्त प्रेषित की गई है। औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। वर्ष 2014-15 में कार्य पूर्ण करने का सतत् प्रयास किया जाएगा। निगम की आय में वृद्धि, जनसुविधा, पर्यटक-आकर्षण, आधुनिकीकरण इत्यादि ध्येयों की पूर्ति होगी।

- नगर निगम शिमला के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय राज्य बस स्टेण्ड टूटीकण्डी-लिफ्ट -रानी झाँसी पार्क रोप वे परियोजना के लिए HPIDB द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने का कार्य प्रगति पर है ।वर्ष 2014-15 के अन्त तक इस परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा । शहर में ट्रैफिक समस्या में वांछित सुधार व इसके अतिरिक्त स्थानीय जनता एवं पर्यटक इस परियोजना से लाभान्वित होंगे ।

- नगर निगम ने हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के सहयोग से रू. 163 करोड़ 52 लाख की अनुमानित लागत से प्रस्तावित आई.जी.एम.सी. से हिमफेड पैट्रोल पम्प टनल तथा सर्कुलर रोड़ के साथ लगते पैदल रास्तों के निर्माण हेतु रू. 12 करोड़ 58 लाख की योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है । भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ओवर ब्रीज बनवाने तथा शहर की सड़कों, सम्पर्क मार्गो एवं रास्तों के कायाकल्प की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2014-15 में धन का प्रावधान होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी ।

- आगामी वित्त वर्ष में लगभग रू. 2 करोड़ की लागत से सड़कों, सम्पर्क मार्गो तथा रास्तों का निर्माण एवं रख-रखाव प्रस्तावित है । लगभग 2000 रेलिंग व 500 बैंच भी स्थापित किए जाएंगे । स्ट्रीट लाईटों की मुरम्मत के लिए तथा नई स्ट्रीट लाईट प्वाईटस के लिए लगभग रू. 2 करोड़ की धनराशि व्यय की जाएगी ।

- रानी झाँसी पार्क में लगभग रू 4 करोड़ की लागत से कृत्रिम बर्फ स्केटिंग, स्पोटर्स, डांसिंग इत्यादि का टर्फ तैयार कर स्थानीय लोगों व पर्यटकों के लिए विशेषतया महिलाओं एवं बच्चों के मनोरंजन का साधन तैयार किया जाएगा ।

- कसुम्पटी क्षेत्र में नगर निगम तथा राजभवन के संयुक्त प्रयासों से लगभग रू. 1 करोड़ की लागत से एक सुनियोजित पार्क का निर्माण प्रस्तावित है जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा तथा सौन्दर्यकरण की राह में मील का पत्थर सिद्ध होगा ।

- नगर निगम शिमला द्वारा वर्तमान में 15 कार पार्किग तथा 5 रोड़ साईड पार्किग चलाई जा रही है । जिनसे वार्षिक रू. 1 करोड़ 20 लाख की आमदनी हो रही है ।

वर्ष 2014-15 में 5 पार्किंग गृह रक्षा विभाग के माध्यम से एवं सी.सी.टी.वी कैमरा, बूम बेरियर, एल.ई.डी. स्क्रीन, कम्पयुटर जैनेरेटिड रसीद इत्यादि की सुविधा सहित चलाने की प्रस्तावना है ताकि शहरवासियों एवं पर्यटकों को सुविधा प्रदान की जा सके।

- कम जगह में अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 में बहुमंजिल स्मार्ट पार्किंग बनाने की भी प्रस्तावना है।

- नगर निगम शिमला की परिधि में लगभग 5000 वाहनों की क्षमता वाले 61 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है तथा भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया प्रगति पर है। औपचारिकताएं पूर्ण होने पर पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। पर्यटक सूचना केन्द्र के समीप पर्यटन विभाग के साथ से लगभग 1000 वाहनों की पार्किंग का निर्माण आरम्भ किया जाएगा।

- नगर निगम द्वारा लोकल बस स्टेण्ड के नजदीक पुराने भवन का पूनर्निमार्ण करवाया जाना प्रस्तावित है । जिसके लिए औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। इसके अतिरिक्त दीन दयाल उपाध्याय हस्पताल की निर्माणाधीन भवन में दो मंजिलों पर नगर निगम द्वारा व्यवसायिक परिसर का निमार्ण किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है।

- नगर निगम शिमला के अधीन सभी पुस्तकालयों/वाचनालयों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा पठन सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगीं।

- वर्ष 2014-15 में सभी वार्ड कार्यालयों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार प्रस्तावित है तथा उनका आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ फर्नीचर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

- युवाओं के लिए खेल-कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वार्ड स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

- संजौली/ईजनघर में स्थित कामकाजी महिला हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा।

- शहर में पॉच चिन्हित क्षेत्रों में लगभग रू.10 लाख की लागत से भीत चित्र (Murals) बनाए जाएंगे।

- विभिन्न संस्थानों की Coporate Social Responsibility (CSR) तथा CBO's /RWA's के सहयोग से पार्को का निर्माण तथा रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

- रानी झॉसी पार्क में सजावटी पौधों तथा फूलों की नर्सरी स्थापित की जाएगी।

- शहर में स्थित श्मशानघाटों, कब्रिस्तान तथा समीट्री के रख-रखाव,सौंदर्यकरण तथा उन्हें सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

- शहर में स्थित महानुभावों की प्रतिमाओं की आवश्यकतानुसार मुरम्मत कर इन्हें समरूप किया जाएगा तथा फॉकस लाईट लगाई जाएंगी।

- सड़कों पर आधुनिक गति अवरोधक, रिफलैक्टर्ज, रोड़ डिवाईडर्ज, केटस आईज इत्यादि लगाकर इनका सौंदर्यकरण किया जाएगा तथा सुरक्षित बनाया जाएगा। सिइनेजिज (signages) तथा गति सीमा सम्बन्धित बोर्ड लगाए जाएंगे।

2. सोलर सिटी :

- नगर निगम शिमला में रू. 2 करोड़ 80 लाख की लागत से सोलर सिटी मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इसके अर्न्तगत शहर के विभिन्न वार्डो में 1000 स्ट्रीट लाईटें लगाने का कार्य जारी है, जिसे अप्रैल,2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। पंचायत भवन शिमला में 15 के.डब्लयु.पी. तथा रिज मैदान पर 20 के. डब्लयु.पी. के एस.पी.वी. पावर प्लॉट की स्थापना,सौर कुकिंग सिस्टम की हि0प्र0 विश्वविद्यालय तथा वर्किग वूमैन होस्टल संजौली में स्थापना, लालपानी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लॉट में हाईड्रो पावर प्लॉट,5000 एस.पी.वी. लालटेन तथा 2000 एस.पी. वी. होम लाईटिंग सिस्टम का प्रावधान आगामी वित्त वर्ष में किया जायेगा।

3. शहरी गरीब के लिए परियोजनाएं :

- राजीव आवास योजना के अर्न्तगत भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सौजन्य से कृष्णानगर पायलट प्रौजेक्ट के लिए स्वीकृत रू. 33 करोड़ 99 लाख 65 हजार की कुल धनराशि में से प्रथम किश्त रू. 10 करोड़ 67 लाख 24 हजार नगर निगम को प्राप्त हुई है। प्रस्तावित 300 आवासीय इकाईयों मे से 224 पात्र चिन्हित लाभार्थियों के लिए तथा 76 किराये के लिए है। रू. 25 लाख की लागत से बनाए जाने वाले पार्क, 1 करोड़ 39 लाख 28 हजार की लागत से बहुउद्देशीय परिसर, रू. 11 करोड़ 89 लाख 60 हजार की लागत से 168 आवासीय इकाईयों तथा लगभग रू. 1 करोड़ 50 लाख की लागत से प्रस्तावित बायपास से होटल होली डे होम सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं तथा निविदाएं आमन्त्रित की गई है । शेष कार्य हेतु निविदाएं फरवरी, 2014 में ही आमन्त्रित करके निर्माण कार्य तीव्र गति से आरम्भ करने की समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के अन्त तक 80 प्रतिशत लाभार्थियों को आवास सुविधा प्रदान की जाएगी तथा शेष कार्य अक्तूबर 2015 तक पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृष्णानगर में सीवरेज व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज सिस्टम, नालों, रास्तों, सड़क, डंगों इत्यादि का सुधार करके फायर फाईटिंग सिस्टम एंव ठोस कचरा प्रबन्धन को भी सुदृढ़ किया जाएगा। सामुदायिक उत्प्रेरण सहभागिता तथा स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता से जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्षित प्रयास किया जाएगा।

- कृष्णानगर के पश्चात् द्वितीय चरण में रूल्दूभटठा वार्ड की चार बस्तियों - ईदगाह कलोनी,कोटहिल क्षेत्र,12 घर की लाईन तथा 5 घर की लाईन- को राजीव आवास योजना के अर्न्तगत लाभान्वित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)के लिए कार्य प्रगति पर है। सामुदायिक सहभागिता से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है तथा हि.प्र. वक्फ बोर्ड से भूमि सम्बन्धित मामलों को उठाया गया है । परामर्शदाताओं का चयन अन्तिम चरण में है । वर्ष 2014-15 में इस वार्ड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त कार्यान्वित करने का लक्ष्य है।

- शिमला शहर के चिहिन्त 87 स्लम क्षेत्रों को राजीव आवास योजना के अर्न्तगत लगभग रू. 250 करोड़ की सहायता प्रदान करने हेतु स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन(SFCPOA) तैयार करने के लिए परामर्शदाता(Consultant) ने कार्य आरम्भ कर दिया है जोकि लगभग 3 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा ।स्लम क्षेत्रों के सार्वभौमिक उत्थान के लिए जी.आई.एस.मेपिंग (GIS Mapping) सहित वृहद् कार्य योजना का वर्ष 2014-15 में वित पोषण प्रस्तावित है ।

- रू. 9 करोड़ 99 लाख की लागत से आशियाना-I परियोजना के अर्न्तगत 252 घरेलू इकाईयों के निर्माण हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई है । वर्ष 2014-15 में 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है । 252 घरेलू इकाईयों का निर्माण प्रस्तावित है ।

- रू.14 करोड़ 1 लाख की लागत से 384 घरेलू इकाईयों का निर्माण हिमुडा द्वारा आशियाना-II परियोजना के अर्न्तगत किया जा रहा है । फोरलेन सम्बन्धित समस्या का समाधान होने की दशा में 88 आवासीय इकाईयों का पात्र लाभार्थियों को आबन्टन जून, 2014 तक एवं 88 का वर्ष 2014-15 के अन्त तक कर दिया जाएगा । नगर निगम शिमला द्वारा निर्मित की जानी वाली शेष 208 इकाईयों का निर्माण एवं आबन्टन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ।

4. अन्य परियोजनाएं :

- दाड़नी का बगीचा (कृष्णानगर) में रू. 26 करोड़ 42 लाख की लागत से आधुनिक वधशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । मुख्य भवन के पीछे स्थित घरों का संरक्षण करने के लिए रू. 70 लाख 91 हजार के डंगे लगाए गए तथा रू. 8 लाख 90 हजार की लागत से सम्पर्क मार्ग का निर्माण भी किया गया । आधुनिक वधशाला को अप्रैल, 2014 से पूर्ण क्षमता पर चालू कर दिया जाएगा ।

- भारतीय प्रसंस्करण एंव उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा मांस की दुकानों के आधुनिकीकरण के लिए प्रति दुकान रू. 5 लाख की अनुदान राशि सिविल वर्क तथा इन्स्टूमेण्ट/फ्रीजर इत्यादि की खरीद के लिए प्रदान की जा रही है । इस संदर्भ में दुकान मालिकों को जागरूक करके सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है ।

- एशियन डवैल्पमेण्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के माध्यम से प्रस्तावित Beautification of Mall Road and Restoration of Mall Road Project का कार्य रू. 18 करोड़ की लागत से शीघ्र आरम्भ किया जा रहा है। जिसमें शैलेट डे से लेकर स्केण्डल प्वाईट से रिज मैदान तक स्ट्रीट फर्नीचर, फेसाड इम्प्रुवमेण्ट, वर्षा शालिका, प्याऊ, कम्बरमेयर ब्रिज फाउन्टेन, स्ट्रीट एवं फॉकस लाईटिंग, रिटेनिंग वाल का सौन्दर्यकरण वेस्ट-बिन (waste bin) इत्यादि का कार्य सड़क तथा ड्रेनज की इम्प्रुवमेण्ट के साथ किया जाएगा। रानी झांसी पार्क तथा दौलत सिंह पार्क का भी सौन्दर्यकरण प्रस्तावित है।

- पर्यटन एंव नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से माल रोड़ की तर्ज पर बालूगंज से छोटा शिमला तथा संजौली से रिज, रिज से जाखू इत्यादि सड़कों का सुधार तथा सौन्दर्यकरण की प्रस्तावना है। विभाग के सौजन्य से शहर में लगभग 35 स्थानों पर दिशासूचक तथा ज्ञानवर्द्धक signages लगाए जाएंगे। तीन प्रमुख स्थानों पर ऐसक्लेटरज लगाने की भी प्रस्तावना है।

- माल रोड़ की तर्ज पर लोअर बाजार, मिडल बाजार, सब्जी मण्डी, गंज बाजार एवं राम बाजार की सड़को के सुधार व सौन्दर्यकरण हेतु भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। जिसे पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के माध्यम से धन उपलब्ध करवाकर कार्यान्वित करने की प्रस्तावना है।

- युरोपियन युनियन के सहयोग से 42 माह की समयावधि तथा 1 मिलियन यूरो की लागत वाली परियोजना चलाई जा रही है। अब तक रू. 1 करोड़ 27 लाख की प्राप्ति हुई है। सामुदायिक केन्द्र न्यू शिमला में कार्यालय को आधुनिक उपकरण,फर्नीचर व स्टाफ प्रदान किया है तथा कार्यकलाप जैसे वर्ल्ड टायलैट डे (19.11.2011), विशेष स्वच्छता अभियान (19-25 नवम्बर), गणतन्त्र दिवस झॉकी, कसुम्पटी में लगभग 800 घरों व संस्थानों का सर्वेक्षण इत्यादि जारी है। परियोजना के अर्न्तगत नगर निगम शिमला के साथ-साथ मण्डी, धर्मशाला, नाहन, हमीरपुर के शहरी निकायों को प्रशिक्षण, वार्ड स्तरीय नियोजन, कसुम्पटी वार्ड में Decentralized Waste Water Treatment System, सार्वजनिक शौचालय का प्रावधान इत्यादि गतिविधियॉ वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित है।

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अर्न्तगत शहर के चहुँमुखी, बहुआयामी एवं सुनियोजित विकास के लिए तैयार किए गए तथा 9 मार्च 2007 को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शहरी विकास योजना (CDP) का सामयिक संशोधन किया जा रहा है। सभी सटैक होल्डर विभागों/संस्थाओं/संस्थानों से गहन विचार-विमर्श के पश्चात, जी.आई.एस.मेपिंग, सैटेलाईट इमेजरी इत्यादि आधुनिकतम तकनीकों के सहयोग से यथार्थवादी शहरी विकास योजना (CDP) को जुलाई 2014 तक मूर्त रूप दिया जाएगा ताकि समग्र, संतुलित एवं सकल विकास के साथ decongestion तथा ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

- नगर निगम द्वारा जमर्नी बेसड के0एफ0डब्लयू0 डलैल्पमैण्ट बैंक से ऋण लेकर शहर में पिंक टैक्सी चलाने की योजना प्रस्तावित है । यह पिंक टैक्सियॉ भटटाकूफर, संजौली से लक्कड़ बाजार, कमला नेहरू हस्पताल, रिटस, हाई कोर्ट, न्यु शिमला, फागली, समरहील, चक्कर, टुटीकण्डी क्षेत्रों से चलाई जाएगी। जिससे विशेष तौर पर महिलाओं, बुजुर्गों व अन्य को सुविधा प्रदान होगी।

- यूरोपियन युनियन, ICLEI व MuAN के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम क्षेत्र में जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2014 की अवधि में SUNYA परियोजना चलाई जा रही है। इसके अर्न्तगत यूरो 1,25,000 की धनराशि का प्रावधान है । निगम के कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि, सुपरवाईजर एवं गारबेज कुलैक्टर को प्रशिक्षण, सैहब सौसाईटी को वित्तीय सहायता, वर्ष 2014 का ज्ञानवर्द्धक कैलेन्डर इत्यादि के साथ-साथ बालूगंज वार्ड Waste Segregation at Source तथा स्थानीय कूड़ा ट्रीट करके खाद बनाने का कार्य प्रस्तावित है।

- ICLEI South Asia के तत्वाधान में शहर में Low Emission Strategies के प्रतिपादन हेतु Urban LEDS परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है जिससे भविष्य में कार्बन क्रेडिट हेतु निगम की दावेदारी प्रबल होगी।

- भारत तथा जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अर्न्तगत जी.आई.जेड. नगर निगम को सहायता प्रदान कर रहा है। पुलिस लाईन भराड़ी में रू. 20 लाख की लागत से Decentralized Water Treatment System(DEWATS)

का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Draft Wastewater Reuse Byelaws बनाये जा रहे है, पलम्बर्ज को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, शौचालयों के नवनिर्माण/रख-रखाव की डी.पी.आर. बनाई गई है, शिमला शहर में सेपटेज मैनेजमेण्ट पर अध्ययन किया जा रहा है, स्वच्छता सम्बन्धित परिस्थितियों तथा पानी की गुणवता में सुधार हेतु 13 स्कूलों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त सेनीटरी लेण्डफिल साईट की पूर्ण निविदा प्रक्रिया में सहयोग, सैहब सौसाईटी पर केस स्टडी, कूड़ा ढ़ोने वाली गाड़ियों का लोडिंग तथा रूटिंग प्लान, सर्विस लेवल बैंचमार्किंग का कार्य भी किया गया है।

- नगर निगम के विशेषतः सफाई कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों का स्वास्थ्य परिक्षण तथा capacity building की जाएगी।

5. जल विभाग :

- शिमला शहर में 130 सार्वजनिक शौचालय हैं,जिनमें से 110 का रख-रखाव सुलभ इण्टरनैशनल संस्था द्वारा किया जा रहा है। जी.आई.जेड. के सहयोग से 26 शौचालय के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2014-15 में शौचालयों के रख-रखाव हेतु कल्सटर बेसिज पर निविदाएं आमन्त्रित करने की प्रस्तावना है । जन शिकायत निवारण हेतु एस. एम.एस. द्वारा शौचालयों से सम्बन्धित सुझाव भी आमन्त्रित किए जाएंगे।

- चालू वित्त वर्ष में 6 नए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया तथा 6 अन्य का निर्माण प्रगति पर है तथा रिज, लालपानी, नजदीक शेरे पंजाब, भराड़ी नजदीक गवर्नमेण्ट स्कूल, लोअर खलीनी, न्यु शिमला सेक्टर-2, सब्जी मण्डी से नीचे तथा संजौली चौक पर सार्वजनिक शौचालय का जिर्णोद्धार किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 में नजदीक लिफ्ट, घोड़ा सराए, जाखू मन्दिर, अनाडेल चौक, नजदीक ताराहाल स्कूल, मोती मस्जिद लोअर बाजार, केथू बाजार तथा कच्ची घाटी में नए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है।

- नगर निगम द्वारा शहर में 39 सार्वजनिक शौचालयों के जिर्णोद्धार पर राशि रू. 66 लाख का व्यय किया जायेगा ।

- नगर निगम शिमला में रिज मैदान पर लगभग रू. 17 लाख की लागत से महिलाओं, पुरूषों एवं बच्चों के लिए तीन ई.-शौचालय का निर्माण वर्ष 2014-15 में पूर्ण किया जाएगा।

- चालू वित्त वर्ष में पानी के बिलों से 31.12.2013 तक रू. 8 करोड़ 64 लाख की आय हुई जोकि आगामी वित्त वर्ष में बढ़कर लगभग रू. 13 करोड़ हो जाएगी।

- चालू वित्त वर्ष में नगर निगम शिमला में सम्मिलित नए क्षेत्रों में 759 नए पानी के कुनैक्शन तथा 244 सीवरेज के कुनैक्शन लगाए गए है, जिससे शहर में 27124 पानी के तथा 10512 सीवरेज कुनैक्शन हो गए है।

- चालू वित्त वर्ष में पानी की लाईनों को बिछाने तथा सुधार हेतु रू. 1 करोड़ 51 लाख तथा सीवरेज व्यवस्था के लिए रू. 2 करोड़ 11 लाख व्यय किए गए। शौचालय निर्माण पर रू. 38 लाख 92 हजार व्यय किए गए है। तवी स्थित टैंक को चालू करके तथा नई वितरण लाईने बिछाकर टूटू क्षेत्र में पानी के कुनैक्शन दिए गए है।

- लगभग रू. 1 करोड़ की लागत से संजौली भण्डारण टैंक को कसुम्पटी टैंक से एक नई लाईन बिछाकर जोड़ा गया है।

- संजौली में ढिंगुधार पम्प में क्षमता सुधार तथा भण्डारण टैंक का निर्माण करके रू. 75 लाख की राशि व्यय कर सितम्बर,2014 में चालू करने की प्रस्तावना है।इससे संजौली, ढली व चम्याणा वार्डो में जल आपूर्ति सुचारू की जाएगी।

- वर्ष 2014-15 में लगभग रू. 14 लाख की लागत से टका बैंच तथा महात्मा गॉधी की प्रतिमा के समीप तीन फवारें लगाए जाने प्रस्तावित है।

- नगर निगम शिमला की परिधि के भीतर तथा बाहर पेयजल आपूर्ति की घरेलू तथा व्यवसायिक दरों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

6. स्वास्थ्य विभाग :

- रू.16 करोड़ 4 लाख की ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना के अर्न्तगत भरियाल में स्थापित संयत्र ने वर्ष 2013-14 में कार्य शुरू कर दिया है। संयत्र के बेहतर प्रबन्धन तथा क्षमता संवर्धन की ओर वर्ष 2014-15 में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- रू. 10 करोड़ 50 लाख की लागत से सेनीटरी लेण्डफिल साईट का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 मे पूर्ण किया जाएगा ताकि अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्धन किया जा सके।

- वर्ष 2013-14 में 29 लाख 30हजार 636 रूपये लागत से 4 पिकअप तथा 2 बोलेरो केम्पर गाड़ियाँ प्राप्त की गई। लगभग रू. 18 लाख का एक बैक हो लोडर तथा रू. 17 लाख का एक स्कीड स्टीयर लोडर तथा लगभग 45 लाख के दो कम्पेक्टर खरीदे गए। 2014-15 में दाड़नी का बगीचा में रू. 20 लाख की लागत से ट्रान्सफर स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है, रू.10 लाख की ट्रक चैसिज, रू. 30 लाख के चार ट्रान्सफर कनटेनरज, रू. 26 लाख के 2 हुक लिफ्ट सिस्टम, रू. 11 लाख के 2 होपरज खरीदने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त 1 मकैनिकल स्वीपर व 5 मॉप अप वेनज खरीदने का प्रावधान भी किया गया है, जिसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा । उपरोक्त प्रावधानों से न केवल ठोस कचरा प्रबन्धन में कार्यकुशलता आएगी अपितु शहर के सौन्दर्यकरण पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। एक सेपटेज डिसपोजल व्हीकल की फेबरीकेशन करके उसे जनू, 2014 तक कार्य में लगाया जाएगा ताकि सीवरेज सुविधा रहित क्षेत्रों में मल निकासी का वैज्ञानिक प्रबन्धन हो सके।

- सैहब सोसाईटी जोकि वर्ष 2009 में गठित की गई थी, में वर्तमान में 526 कर्मचारी कार्यरत हैं। सोसाईटी के माध्यम से डोर टू डोर गारबेज कुलैक्शन,स्ट्रीट स्वीपिंग तथा गारबेज डिस्पोजल का काम किया गया है। इस समय शहर में 35263 इकाईयों से कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है तथा प्रतिमाह 22-25 लाख की धनराशि एकत्रित हो रही है। आगामी वित्त वर्ष में शहर की सभी इकाईयों को सैहब सोसाईटी के दायरे में लाना प्रस्तावित है तथा सभी कर्मचारियों को ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- सैहब सौसाईटी के कर्मचारियों को केरीबेगज,नई वर्दी तथा जूते इत्यादि प्रदान किए जाएंगे।

- कूड़े का वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु विकेन्द्रीयकृत प्लॉट लगाए जाने की प्रस्तावना है जिससे स्थानीय स्तर पर ईंधन (Bio-Diesel Gas) उर्जा एवं खाद इत्यादि की आवश्यकता पूर्ण की जा सके। प्रयोगात्मक तौर पर कामकाजी महिला हॉस्टल,स्लाटर हाउस तथा सब्जी मण्डी में यह कार्य प्रस्तावित है।
- शहर के डम्पर आवश्यतानुसार बदले जाएंगे।

7. सम्पदा विभाग :

- रेहड़ी, फड़ी व फेरी वालों तथा केन्द्र सरकार से तहबाजारियों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास हेतु शिमला शहर के लिए 3 करोड़ 85 लाख 53 हजार रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृत प्रदान करवाई है। लिफ्ट के समीप बैकरी बिल्डिग के स्थान पर पार्किंग तथा लिफ्ट सुविधा सहित 222 दुकानें बनाने की प्रस्तावना है, जिनका आबन्टन 168 पंजीकृत तहबाजारियों सहित पात्र चयनित लघु व्यवसायियों को वर्ष 2014-15 के अन्त तक कर दिया जाएगा। शहर के बीचों बीच प्रस्तावित परिसर में सौर उर्जा पर आधारित तकनीक, शौचालय,वर्षा जल संग्रहण व ठोस कचरा प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था होगी। भवन निर्माण एवं दुकान आबन्टन के उपरान्त ऐतिहासिक स्कैण्डल प्वाईट से लक्कड़ बाजार बस अड्डा ऐम्बुलैंस मार्ग को पुनः आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। तहबाजारियों की सहभागिता से उनके कौशल विकास, बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण तथा लघु व्यवसायियों के बच्चों को शिक्षा एवं सभी को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

- Town Vending Committees के पुनर्गठन के उपरान्त National Street Vendors Policy,2009 तथा Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012 के प्रावधानों के अनुसार शहर में Vending Zones,No Vending Zones तथा Restricted Vending Zones को चिन्हित किया जाएगा ताकि लघु व्यवसायियों के पुनर्वास के साथ-साथ जनसुविधा को भी पूर्ण अधिमान दिया जा सके तथा उनके लिए अन्य चिन्हित स्थानों पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा।

- वर्तमान में नगर निगम शिमला की परिधि में 5 लेबर होस्टल चल रहे हैं, जिनमें लगभग 450 श्रमिक रहते हैं । चालू वित्त वर्ष में इन लेबर होस्टलों की मुरम्मत हेतु रू. 14 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2014-15 में एक नए लेबर होस्टल का निर्माण हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग के सौजन्य से कोटहिल में प्रस्तावित है। दो और लेबर होस्टल के लिए भी स्थान चयनित किया जा रहा है तथा इसका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। श्रमिकों के बिजली बिलों को हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लि0 से मामला उठाकर व्यवसायिक से घरेलू दर पर करने की भी प्रस्तावना है।
- Corporate Social Responsibility के अर्न्तगत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया व पंजाव नेशनल बैंक के सौजन्य से श्रमिको की सुविधा के लिए लेबर होस्टल नजदीक मरीना होटल, जामा मस्जिद व मोती मस्जिद में नगर निगम द्वारा इन स्थानों पर 500 लीटर क्षमता के 3 सोलर गीजर लगवाये गये है। जिस पर बैंक के द्वारा लगभग 2.50 लाख खर्च किए गए है।

- दुकानों की लाईसैंस प्रक्रिया का सरलीकरण करके इसे गति प्रदान की जाएगी ताकि अनावश्यक समय नष्ट न हो तथा इसे ई0गवर्नेस से जोड़ा जाएगा।

- वर्ष 2013-14 में नगर निगम को विज्ञापन/होर्डिग्स स्थलों से लगभग रू. 50 लाख की आमदनी प्राप्त हुई है। वर्ष 2014-15 में नई विज्ञापन नीति बनाई जानी प्रस्तावित है ताकि अधिक स्थलों को चिन्हित कर लगभग रू. 3 करोड़ की आमदनी प्राप्त की जा सके। इस संदर्भ में Delhi Integrated market Model Transit System (DIMTS) के साथ वार्ता जारी है, जिसे मई, 2014 तक अन्तिम रूप दिया जाएगा।

- विभिन्न फिल्मों की शूटिंग से चालू वित्त वर्ष में रू. 7 लाख 15 हजार की आय प्राप्त हुई हैं वर्ष 2013-14 में माननीय सदन द्वारा इस प्रयोजनार्थ शुल्क को संशोधित किया गया है ताकि आगामी वित्त वर्ष में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देकर लगभग रू. 10 लाख की आय सृजित करने की प्रस्तावना है।

- वर्ष 2013-14 में निगम की दुकानों की सबलैंटिग के नियमितिकरण हेतु माननीय सदन द्वारा नीति निर्धारित की गई है। इसके अर्न्तगत दुकानों के किराए में वृद्धि, रू. 1 करोड़ की एक मुश्त राशि प्राप्त होने तथा व्यवसायियों को आर्थिक एवं मानसिंक राहत प्रदान करने के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हुई है।

8. वास्तुक विभाग :

- चालू वित्त वर्ष में वास्तुक योजनाकार शाखा के माध्यम से 468 मामलों में भवनों के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा विभिन्न प्रकार के शुल्को/पैनल्टी/अनापति प्रमाण पत्रों से लगभग रू. 2 करोड़ 60 लाख की आय प्राप्त हुई है। आगामी वित्त वर्ष में ई0 गवर्नेस परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात ऑन लाईन भवन निर्माण हेतु नक्शों को जमा करवाने तथा स्वीकृति की सुविधा प्रदान की जाएगी।

9. स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना :

- नगर निगम शिमला के अर्न्तगत वर्ष 1998 से कार्यान्वित स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना के अधीन 2126 बी.पी.एल. परिवार चयनित किए गए है। चालू वित्त वर्ष में NGO's/CBO's /Empanelled Agencies/NIELIT के तत्वाधान में लगभग 750 शहरी गरीब लाभार्थियों को artificial Jewellery making, beautician, cutting-tailoring, plumber, electrician, soft toys making, Tally, Multimedia, hardware, networking इत्यादि में लगभग 20 लाख रूपये की लागत से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 40 शहरी गरीब युवाओं को टुरिस्ट गाईड का प्रशिक्षण भी दिया गया। 235 पात्र लाभार्थियों को रू. 8 लाख का ऋण एवं अनुदान राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से वितरित किया गया ताकि स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। स्वयं सहायता समुहों द्वारा नगर निगम द्वारा प्रदत्त चक्रीय राशि(Revolving Fund) की सहायता से निर्मित उत्पाद रेडक्रास मेला एवं अन्य स्थानों पर प्रदर्शित तथा विक्रय करके अपेक्षा से भी अधिक ख्याति एवं स्मृद्धि प्राप्त की गई । नगर निगम शिमला द्वारा जारी बी.पी.एल. कार्ड का सदुपयोग लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य,शिक्षा,खाद्य एवं आपूर्ति,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का दोहन करने के लिए भी किया जा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत लगभग रू. 6 लाख की लागत से संजौली स्थित कामकाजी महिला हॉस्टल तथा लक्कड़ बाजार लेबर होस्टल का जीर्णोद्धार किया गया।

- वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का भी प्रादुर्भाव हो रहा है। आगामी वित्त वर्ष में लगभग 1000 शहरी युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के समुचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। लगभग 50 स्वयं

सहायता समूहों को क्रियाशील बनाकर, उन्हें बैंकों से जोड़कर, क्षमता वर्द्धन,वित्त पोषण करके लाभान्वित किया जाएगा। ऑकलैण्ड सुरंग के समीप स्थित रैन बसेरा का रू. 30 लाख की लागत से जीर्णोद्धार भी प्रस्तावित है। Placement Linked Skill Upgradation पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

10. सूचना प्रौद्योगिक व ई0 गवर्नेस :

- आगामी वित्त वर्ष में रू. 11 करोड़ 20 लाख की लागत से स्वीकृत ई0 गवर्नेस परियोजना के अर्न्तगत सोफटवेयर तथा हार्डवेयर उपलब्ध करवा कर सभी 22 मॉडयूल को अगस्त, 2014 तक प्रारम्भ किया जाएगा। इससे जनसाधारण को ऑन लाईन सुविधाएं, वार्ड स्तर पर महत्वपूर्ण जानकारियॉ एवं आधुनिक सुविधाएं तथा त्वरित व पारदर्शी कार्य प्रणाली का लाभ प्राप्त होगा तथा नगर निगम की कार्यकुशलता में भी आशातीत वृद्धि होगी।

- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से तथा संचार कम्पनियों की सहभागिता से शहर को समार्ट सिटी बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ जारी संयुक्त प्रयासों को गति प्रदान की जाएगी । महत्वपूर्ण कार्यालयों/संस्थाओं को निःशुल्क कनैक्टीविटी तथा सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई नेटवर्क उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस पग उठाए जाएंगे।

11. प्राप्त सहायता अनुदान :

इस वित्तीय वर्ष में 31.12.2013 तक प्रदेश सरकार के माध्यम से व अन्य स्तरों से नगर निगम को प्राप्त अनुदान राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1	जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से :-		
	क-	डिसेन्ट्रेलाईजड़ प्लानिंग के अन्तर्गत अनुदान	16.58 लाख
	ख-	प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत अनुदान	6.53 लाख
	ग-	शहर में कार्यो हेतू अनुदान	11.24 लाख
2	निदेशक, शहरी विकास विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से :-		
	क-	सड़कों के रख-रखाव हेतू	121.68 लाख
	ख-	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान सहायता	348.75 लाख
	ग-	तृतीय/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान सहायता/चुंगी समाप्ति	564.80 लाख
	घ-	**O&M of Sewerage Scheme under demand No.28** के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि	150.00 लाख
	ड-	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत	5.76 लाख
	च-	अर्बन रिस्क रिडक्शन प्रोग्रम के अन्तर्गत	11.69 लाख
3		विधायक निधि से	14.15 लाख
4		सांसद निधि से	39.50 लाख
5	अन्य विभागों के माध्यम से:-		
	क-	हिमुडा, **EE, I&PH** व साडा शोघी से प्राप्त राशि	55.95 लाख
	ख-	पर्यटन विभाग से हाई मास्ट लाईट लगाने हेतू एव सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेत प्राप्त अनुदान	19.00 लाख
	ग-	एस0जे0वी0एन0एल0 से हाई मास्ट लाईट हेतू प्राप्त राशि	22.41 लाख
	घ-	भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक व अन्य सामाजिक संस्थाओं से बैंच लगाने हेतू प्राप्त राशि	2.00 लाख
6	आधुनिक स्लाटर हाउस के निर्माण हेतू प्राप्त अनुदान :-		884.00 लाख
7	शून्य प्रोजैक्ट के अन्तर्गत अनुदान :-		34.00 लाख
8	**JNNURM** के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान :-		1073.77 लाख
	कुल प्राप्त अनुदान राशि -		3381.81 लाख

12. विकासात्मक गतिविधियों के लिए बजट अनुमानों का विवरण :

(राशि रूपये लाखों में)

क्रम सं0	विवरण	राजस्व (रख-रखाव)	पुंजीगत (निर्माण)	कुल
1	सड़कों, रेलिंग, डंगों, सीढ़ियों, रास्तों इत्यादि के रख-रखाव व निर्माण के कार्यो हेतु	710.00	270.00	980.00
2	स्ट्रीट लाईट लगाने व उनके रख-रखाव हेतु	75.00	125.00	200.00
3	निगम के भवनों, आवासों के रख-रखाव / निर्माण हेतु	120.00	225.00	345.00
4	पार्किंग का रख-रखाव व निर्माण हेतु	20.00	50.00	70.00
5	नालों की चैनेलाईजेशन/ मुरम्मत/ निर्माण हेतु	30.00	110.00	140.00
6	पानी की अतिरिक्त लाईनों को बिछानें, उनके रख-रखाव हेतु	30.00	132.00	162.00
7	सिवरेज लाईनें बिछाने व रख-रखाव हेतु	30.00	300.00	330.00
8	शौचालय के निर्माण/रख-रखाव हेतु	75.00	100.00	175.00
9	पार्क इत्यादि विकसित करने हेतु	21.00	15.00	36.00
10	लेबर होस्टल का निर्माण	-	150.00	150.00
11	शहर में नये डम्पिंग स्थान बनाने हेतु	-	150.00	150.00
12	सौलिड बेस्ट मैनेजमैन्ट	210.00	-	210.00
कुल योग :-		1321.00	1627.00	2948.00

13 नगर निगम शिमला के वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान :

नगर निगम शिमला के वर्ष 2013-14 के संशोधित एवं आगामी वित्त वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों का मुख्य शीर्ष-बार विवरण निम्नानुसार है :-

(Rs. in lakhs)

Major Account Head Code	Actual for the previous year 2012-13 ₹	Budget Estimates for the year 2013-14 ₹	Actual of First Nine Month for current year 2013-14 ₹	Revised Estimates for the current year 2013-14 ₹	Budget Estimates for the next year 2014-15 ₹
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व आय					
110- Tax Revenue	**258.15**	**1503.00**	**633.60**	**652.60**	**1502.88**
मुख्य शीर्ष 110-सम्पत्ति कर के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में सम्पत्ति करों से 1502.88 लाख रूपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
120- Assigned Revenues and Compensation	**1538.96**	**1810.00**	**613.57**	**1822.03**	**1985.10**
मुख्य शीर्ष 120- Assigned Revenues & Compensation के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 1775.10 लाख, बिजली की खपत पर फीस से 150.00 लाख व शराब की बिक्री पर फीस से 60.00 लाख रूपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
130- Rental Income- Municipal Properties	**311.43**	**271.15**	**271.20**	**524.13**	**320.00**
मुख्य शीर्ष 130- निगम की दुकानों/स्टालों आदि से किराए के रूप में आगामी वित्त वर्ष में 320.00 लाख रूपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
140- Fees & User Charges	**1801.44**	**2543.71**	**1702.48**	**2077.42**	**2875.47**
मुख्य शीर्ष 140- फीस एण्ड यूजर चार्जिज के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में Water Charges से 1300.00 लाख, सीवरेज यूजर चार्जिज से 100.00 लाख, Compounding फीस से 500.00 लाख, ग्रीन फीस से 300.00 लाख, पार्किंग फीस से 120.00 लाख, विज्ञापन एवं होर्डिगं चार्जिज से 100.00 लाख डम्पिंग साईट चार्जिज से 110.00 लाख, रोड डैमेज चार्जिज से 100.00 लाख अन्य फीस एवं यूजर चार्जिज से 245.47 लाख रूपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
150- Sale & Hire Charges	**34.72**	**26.00**	**8.56**	**9.96**	**14.00**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में स्टोर में पडे स्क्रैप, कण्डम टिप्पर, डम्पर कन्टेनर की नीलामी व फार्म आदि की बिक्री से 14.00 लाख रूपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
160- Revenue Grant, Contributions & Subsidies	**46.74**	**50.00**	**51.31**	**66.44**	**67.00**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से निगम द्वारा केन्द्र सरकार की कालोनियों में नियुक्त सफाई स्टाफ के वेतन की प्रतिपूर्ति आदि के रूप में आगामी वित्त वर्ष में 67.00 लाख रूपये की प्राप्ति का अनुमान है।					

1	2	3	4	5	6
170- Income from Investments	**111.00**	**50.01**	**46.53**	**50.00**	**50.01**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम निधि से समय-समय पर बैंकों में निवेशित राशि पर ब्याज से आगामी वित्त वर्ष में 50.01 लाख रूपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
171- Interest Earned	**44.62**	**25.65**	**34.20**	**40.84**	**24.48**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत बकाया करों व किराए की राशि पर और बैंक बचत खातों में जमा राशि आदि पर ब्याज से आगामी वित्त वर्ष 24.48 लाख रूपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
180- Other Income	**13.74**	**14.00**	**18.57**	**24.41**	**13.25**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Miscellaneous Income से आगामी वित्त वर्ष में 13.25 लाख रूपये की आय प्राप्ति का अनुमान है।					
योग राजस्व आय (1)	**4160.80**	**6293.52**	**3380.02**	**5267.83**	**6852.19**
उपरोक्त विवर्णानुसार आगामी वित्त वर्ष में राजस्व आय के अन्तर्गत निगम की कुल आय 6847.19 लाख रूपये अनुमानित है।					
2. पूँजीगत आय					
320- Grants, Contributions for Specific purposes	**1367.34**	**10282.03**	**2817.01**	**4450.99**	**4999.44**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य संस्थाओं से मुख्यतः स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अर्न्तगत 50.00 लाख, Merged Area Grant 300.00 लाख, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 300.00 लाख, Maintenance of ULB roads के अन्तर्गत 121.00 लाख, MPLAD/MLALAD/ 5% DCP व अन्य संस्थाओं से 160.00 लाख, JNNURM के अर्न्तगत स्वीकृत प्रोजैक्टों के लिए 3646.30 लाख, शुन्य प्रोजैक्ट के अन्तर्गत 40 लाख और सैनिटेशन सर्विसिज के लिए यूरोपियन यूनियन से 382.14 लाख रूपये की अनुदान सहायता की प्राप्ति का अनुमान है।					
330- Secured Loans	**0.00**	**1902.03**	**0.00**	**0.00**	**801.12**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में JNNURM के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोजैक्टों के लिए निगम के अंशदान के भुगतान के लिए 801.12 लाख रूपये वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की प्रस्तावना है।					
योग पूँजीगत आय (2)	**1367.34**	**12184.06**	**2817.01**	**4450.99**	**5800.56**
उपरोक्त विवर्णानुसार आगामी वित्त वर्ष में पूँजीगत आय के अन्तर्गत निगम की अनुदान आदि से आय 5800.56 लाख रूपये अनुमानित है।					
कुल आय (1+2)	**5528.14**	**18477.58**	**6197.03**	**9718.82**	**12652.75**

1	2	3	4	5	6
3. राजस्व व्यय					
210- Establishment Expenses	**3748.42**	**4863.60**	**2940.63**	**4099.50**	**4546.83**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, पैन्शन अंशदान, सी.पी.एस. अंशदान, ई.पी.एफ. अंशदान, सेवानिवृति से सम्बन्धित अन्य लाभ की अदायगी हेतू आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 4546.83 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत सेवानिवृत कर्मचारियों की पैन्शन के भुगतान हेतू राशि रूपये 439.00 लाख रूपये का अतरिक्त प्रावधान Pension Deficit Contribution के रूप में रखा गया है।					
220- Administrative Expenses	**231.69**	**236.07**	**147.46**	**241.45**	**527.83**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कार्यालय रख-रखाव, बिजली, टैलीफोन, लेखन-सामग्री, फर्नीचर, कम्पयूटर, कन्सल्टैन्सी चार्जिज आदि के प्रशासनिक व्यय हेतू आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 527.83 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।					
230- Operations and Maintenance	**978.97**	**4001.65**	**1215.29**	**1602.91**	**4198.05**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से पानी की खरीद के बिलों के भुगतान, निगम की ढाँचागत परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, आवश्यक नागरिक सुविधाओं व अन्य रख-रखाव के कार्यो हेतू आगामी वित्त वर्ष के लिए 4198.05 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।					
240-Interest and Finance Charges	**0.57**	**1.50**	**0.01**	**0.10**	**0.50**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Interest & Finance Charges हेतू आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 0.50 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।					
250- Program Expenses	**1.45**	**9.00**	**3.57**	**5.50**	**9.00**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Program Expenses हेतू आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 9.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।					
260- Revenue Grants, Contributions and Subsidies	**18.64**	**61.75**	**33.24**	**40.00**	**50.00**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वित्त वर्ष में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से शहरी गरीबों के उत्थान के कार्यक्रमों पर ब्यय आदि के लिए राशि 50.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।					
280- Prior Period Item	**5.45**	**0.50**	**6.61**	**6.61**	**1.00**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत Prior Period Expenses हेतू आगामी वित्त वर्ष के लिए 1.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।					
योग राजस्व व्यय (3)	**4985.19**	**9174.07**	**4346.81**	**5996.07**	**9333.21**
उपरोक्त विवर्णानुसार आगामी वित्त वर्ष में राजस्व व्यय के अर्न्तगत निगम का राजस्व व्यय 9333.21 लाख रूपये अनुमानित है।					

1	2	3	4	5	6
4. पूँजीगत व्यय					
410- Fixed Assets	**1437.60**	**2353.39**	**1484.84**	**1949.85**	**2385.35**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निगम के भवनों, सडकों, नाले-नालियों के निर्माण एवं रख-रखाव, जल वितरण एवं सीवरेज लाईनें बिछाने एवं रख-रखाव, स्ट्रीट लाईट लगवाने एवं रख-रखाव, कार्यालय प्रयोग हेतू फर्नीचर-फिक्सचर एवं अन्य सामग्री की खरीद हेतू आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 1635.35 लाख रूपये, शहर में नए लेबर होस्टल के निर्माण के लिए 150.00 लाख रूपये और पाषदों की प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक बार्ड में विकास कार्यो हेतू राशि 600.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत जे.एन.एन.यू.आर.एम. की गाईडलाईन्ज के अनुरूप कुल बजट प्रावधान का 25 प्रतिशत शहरी गरीबों के लिए नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर व्यय करने का प्रावधान किया गया है।					
412- Capital Work in Progress	**14.00**	**9697.31**	**26.73**	**2610.88**	**3646.30**
इस मुख्य शीर्ष में JNNURM के अन्तर्गत स्वीकृत स्कीमों के तहत प्रगति पर कार्यो के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 3646.30 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।					
430- Stock in hand (Store Purchase)	**0.00**	**407.00**	**132.78**	**150.00**	**300.00**
इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निर्माण सामग्री आदि की खरीद हेतू भण्डार के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए राशि 300.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।					
योग पूँजीगत व्यय (4)	**1451.60**	**12457.70**	**1644.35**	**4710.73**	**6331.65**
उपरोक्त विवर्णानुसार आगामी वित्त वर्ष में निगम का पूँजीगत व्यय 6331.65 लाख रूपये अनुमानित है।					
कुल योग (3+4)	**6436.79**	**21631.77**	**5991.16**	**10706.80**	**15664.86**
	- 908.65	-3154.19	205.87	-987.98	-3012.11
अतः आगामी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में प्रस्तावित आय व व्यय से स्पष्ट है कि निगम का आगामी बजट अनुमान 3012.11 लाख रूपये घाटे का है। इसलिए आगामी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में व्यय के विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत रखा गया प्रावधान निगम की आय पर निर्भर करेगा।					

माननीय सदस्यगण मैने अपने बजट भाषण में नगर निगम की उपलब्धियों, विकास कार्यो, समस्याओं व सुझाव इत्यादि का वर्णन करने का प्रयास किया है तथा आगामी वर्ष के लिये बजट में रखी गई प्रस्तावित राशि का भी वर्णन किया है इन सब बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करना आवश्यक है ।

मैं निगम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरवर्ग के कार्य व सहयोग के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, यथाशक्ति एवं लग्न से अपना-अपना कार्य करते रहेंगे।

अन्त में, मैं अपने समस्त सहयोगी पाषर्दो का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से निगम में नीति निर्धारण, विकास कार्य करवाने, लोगों की समस्याओं को हल करने इत्यादि में आज तक आपका सहयोग रहा है भविष्य में भी आप का सहयोग मिलता रहेगा। सामूहिक कार्य प्रणाली व परस्पर सहयोग से ही शिमला शहर का चहुमुखी विकास करवाना तथा इसकी गरिमा को बनाये रखना सम्भव है।

अतः इन शब्दों के साथ मैं मान्य सदन से वर्ष 2014-15 के बजट पर विचार-विमर्श करने हेतु अनुरोध करता हूँ।

धन्यवाद ।

22 फरवरी, 2014

(संजय चौहान)
महापौर
नगर निगम शिमला